देश के हर नगर व ग्रामांचल में
दैनिक निर्दलीय को प्रतिनिधि चाहिए
पत्रकारिता के साथ सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक-अभिरुचि वालों को प्राथमिकता।
संपर्क करें- 91 8839797448/942443401
निर्दलीय प्रकाशन
फ ११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल ४६२ ०१६

प्रेस पंजीयन एम.पी.एच.आई.एन./२०११/४८५६५

निर्दलीय प्रकाशन का स्वर्ण जयंती वर्ष

निर्दलीय

संपर्क-फ-११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल

निष्पक्षता, निर्वैरता व निर्भयता का दैनिक प्रवक्ता

ई-मेल: nirdaliyadaily@gmail.com

दैनिक निर्दलीय
साप्ताहिक निर्दलीय
और मासिक निर्दलीय
अब तीनों स्वरूपों में वेबसाइट
www.nirdaliya.comपर उपलब्ध
विधिः पहले उक्त लिंक पर जाएं
फिर क्लिक करें
e-paper, इसके बाद दैनिक निर्दलीय जिस तारीख का पढ़ना हो वह तारीख और पृष्ठ संख्या डालें।
साप्ताहिक हेतु weekly निर्दलीय
और मासिक हेतु Magazine निर्दलीय क्लिक करें
निर्दलीय एफ-११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल-४६२०१६

वर्ष-५४/१६ अंक- ५५ | भोपाल, १ सितंबर, डाक २ सितंबर २०२६ | भोपाल व नई दिल्ली से प्रकाशित | पृष्ठ -८ | मूल्य १+१/-(संप्रेषण/स्वैच्छिक)

नींव पढ़ी नफरत की, फैलाते अंधियार। उजियारे के नाम पर, भड़काते अंगार।।

अग्र विचार
विचार प्रवाह-१७९

कैलाश आदमी

हिंदुओं की कट्टरपंथी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का विगत २९ अगस्त को न्यूयॉर्क में वैश्विक एकता उत्सव 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी मुख्य बात यह थी कि भागवत ने कहा कि भारत के जो हिंदू यह सोचते हैं कि देश से मुसलमान निकल जाएं यह सोचने वाले लोग हिंदू नहीं हैं।

उक्त कार्यक्रम न्यूयार्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्थित इन्फोसिस थिएटर में मेरिकी समयानुसार दोपहर २ बजे से शाम ५.३० बजे तक (भारतीय समय के अनुसार रात लगभग ११.३० बजे से ३० अगस्त सुबह ३ बजे तक) चला।

इसकी आयोजक संस्था अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम थी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा था जिसका उद्देश्य संघ की विचारधारा को अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं तक पहुंचाना तथा उनकी गलत फहमियां दूर करना तो था ही, इसके साथ संघ का विचार भारत के बाहर रहने वाले सभी हिंदुओं तक पहुंचाना भी था। इस आयोजन में अमेरिका के २९ राज्यों और करीब ८५३ शहरों से न्यूयार्क आए ५,००० से अधिक भारतीय मूल के अमेरिकी, युवा, छात्र, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि तथा लगभग १८० धार्मिक नेता (३०देशों से) शामिल हुए। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहारों में गिने जाने वाले राखी (रक्षाबंधन) के दूसरे दिन आयोजित यह कार्यक्रम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (दुनिया एक परिवार है) के संदेश पर केंद्रित था।

मोहन भागवत इस सप्ताह की शुरुआत में न्यूयॉर्क पहुंचे थे। यह उनकी अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की वैश्विक संपर्क यात्रा का पहला चरण था। इससे पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में इस्कॉन मंदिर (२६ सेकंड) का दौरा किया और बेघर लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम में भाग लिया।

लगभग ४५ मिनट से अधिक चले भाषण में उन्होंने निम्नलिखित बातें कहीं- एकता और विविधता भारत के डीएनए अर्थात रक्त मूल में है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो बहुलवाद की चर्चा होती है, और जब भारत की बात करते हैं तो 'एकता में विविधता' की। भारत के लिए एकता और विविधता दोनों उसके डीएनए में हैं। विविधता का जश्न मनाना, उसका सम्मान और स्वीकार करना जरूरी है, साथ ही एकता की भावना बनाए रखनी चाहिए।

स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए भागवत ने कहा कि हर राष्ट्र का एक संदेश, मिशन और नियति होती है। भारत का दायित्व है कि वह विविधता में एकता को समझे और समय-समय पर दुनिया को इसका अहसास कराए—सिर्फ उपदेश से नहीं, बल्कि व्यवहार से। अगर कोई हिंदू सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह सकता। हिंदू होने का मतलब है कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं और हर इंसान की गरिमा समान है। उन्होंने अमेरिकी भारतीय समुदाय से अपील की कि वे अपनी कर्मभूमि (अमेरिका) के प्रति वफादार रहें, कमाएं और वहां के प्रति सच्चे रहें, लेकिन जन्मभूमि (भारत) से मिले मूल्यों—खासकर एकता की भावना—को बनाए रखें। धर्म को सिर्फ पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने वाला सिद्धांत बताया। जियो और जीने दो की प्रवृत्ति को सही बताया, जबकि सिर्फ आज्ञा मानने वालों की रक्षा करने वाले को राक्षस कहा। कार्यक्रम में अंतरधार्मिक नेता (रबि, इमाम, रेवरेंड आदि) भी मंच पर थे जिन्होंने एकता, करुणा तथा सहयोग के संदेश दिए।

ज्ञातव्य है कि न्यूयॉर्क के महापौर जोहरान ममदानी ने कार्यक्रम का समर्थन नहीं किया बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की दृष्टि को बहिष्कारवादी दृष्टि बताते हुए कहा था कि यदि उनके अधिकार में होता तो वे भागवत को न्यूयार्क में घुसने ही नहीं देते। कुछ मानवाधिकार और अंतरधार्मिक संगठनों ने भी विरोध जताया। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था सीआईआरएफ ने भी कुछ आपत्तियां जताई थीं। फिर भी कार्यक्रम निजी होने के कारण आयोजित हुआ और निर्धारित संख्या में लोग पहुंचे।

यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों और अंतरधार्मिक संवाद को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा बताया गया। मेरे विचार से भागवत ने मुसलमानों के बारे में जो कुछ कहा वह संघ के पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों के आचरण व व्यवहार के सर्वथा विपरीत था। वस्तुतः संघ भारत में गैर हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने का काम करता रहा है। संघ की ओर से कहा जाता है कि यह संगठन पूरी तरह राजनीतिक है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि संघ ने आजादी के पूर्व अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और उसके स्वयं सेवक भारतवासियों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में जाने हेतु प्रेरित करते थे तथा आम नागरिकों को कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अधिनायक विरोधी अभियान से दूर रहने की बात करते थे। अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने की घोषणा की तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने कहा कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। इस कारण भारत का बंटवारा हुआ जिसके दंश हम आज तक भुगत रहे हैं। संघ इन जख्मों को कुरेदने का काम करता रहा है तथा भागवत की यात्रा इसी उद्देश्य को लेकर आयोजित की गई।

अंत में मेरी दो काव्य पंक्तियां-

नींव पढ़ी नफरत की, फैलाते अंधियार।
उजियारे के नाम पर, भड़काते अंगार।।

उठते कदम परिवर्तन का संकेत?

निर्दलीय विशेष/
शशिकांत गुप्ते

निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय। इस दोहे में संत कबीर ने निंदक का महत्व क्यों है? यह दार्शनिक अंदाज में समझाया है। व्यवहारिक दृष्टि से उक्त दोहा लोकतंत्र की बुनियाद असहमति की तस्दीक करता है। देश के हर एक नागरिक को सत्ता के द्वारा घोषित कोई भी जनविरोधी नीति या किसी भी जनविरोधी योजना की निंदा करने संवैधानिक अधिकार है। निंदा मतलब ही अपनी असहमति को दर्शना होता है।

दुर्भाग्य से इन दिनों असहमति को देशद्रोह माना जा रहा है। यह व्यवस्था के अलोकतांत्रिक सोच को दर्शाता है। संत कबीर साहब तो निंदक को अपना परम हितैषी मानते हैं। यदि कोई निंदक आपकी निंदा करता है मतलब वह आपकी व्यक्तिगत निंदा नहीं करता है बल्कि वह आपकी गलतियों को उजागर करता है। और आपको उन गलतियों को सुधारने की प्रेरणा मिलती है।

वर्तमान में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, एक तो चोरी उपर से सीना जोरी यह कहावत चरितार्थ हो रही है। राजनीति में गलतियां गालियां,मिथ्या आरोप, कुतर्क,इतिहास को तोड़ फोड़ कर प्रस्तुत करना,स्वतंत्रता सैनानियों का अपमान करना,देश के प्रथम प्रधानमंत्री की दिन रात आलोचना करना। एक मिथ्या गप का प्रचार भी बहुत किया जा रहा है,की सन 2014 के पूर्व 70 वर्षों में देश में कुछ हुआ ही नहीं? लेकिन 2014 के बाद पहली बार लोकतंत्र का पवित्र कहलाने वाला मंदिर मतलब देश की संसद में गांधीजी के हत्या करने वालें व्यक्ति को सम्मान से नवाजा गया,पहली बार एक संसद सदस्य ने विधर्मी विपक्षी संसद सदस्य को असंसदीय शब्दों के साथ बेख़ौफ़ होकर जलील किया गया।

अनजाने में यदि किसी से गलती होती है,तो वह क्षम्य है। लेकिन जानबूझकर की जाने वाली गलतियों की तो घोर निंदा की जानी चाहिए। अच्छे दिन अमृत काल भी पंद्रह लाख का जुमले साबित हो रहें हैं।

सत्ता के मद मदहोश होकर यह नहीं भूलना चाहिए कि अति का अंत सुनिश्चित है। परिवर्तन की लहर इन दिनो सड़को पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। देश का भविष्य मतलब देश के नौनिहालों ने अपनी जागृति का प्रमाण देना शुरू कर दिया है। जेन जी के बाद जेन अल्फा भी अब सड़कों पर उतर आएं हैं। समाजवादी चिंतक,विचारक, स्वतंत्रता सैनानी डॉ.राममनोहर लोहिया जी का कथन आमली रूप ले रहा है। लोहिया जी कहा था कि जब सड़क खामोश होती है तब संसद आवारा हो जाती है। आज सड़क गर्म हो रही है संसद हिलने लगी है। इतिहास गवाह है जब जब भी आंदोलन में युवा शिरकत करता है तब तब क्रूर से क्रूर तानाशाह की सत्ता भी डगमगाने लगती है। देश की युवा पीढ़ी का जागृत होकर अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए सक्रिय होना और सक्रियता भी अहिंसक होना भी लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है।

-इंदौर

रचनाएं आमंत्रित हैं
नई दिल्ली से प्रकाशित
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका
'निर्दलीय'
सितंबर माह के आरंभ में प्रकाशित होने जा रहे विशेषांक का विषय है –
किशोरों की दशा और दिशा
(संदर्भ जेन जी/जेन अल्फा आंदोलन)
इस विशेषांक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रित करत हुए नई सोच, कुंठा, घुटन, संत्रास और संवेदना को अपनी मौलिक और अप्रकाशित समसामयिकता से जुड़े आलेख/ समालोचना, संस्मरण, कहानी, लघुकथाएँ, गीत, ग़ज़ल, कविताएँ, ३१ अगस्त तक सादर आमंत्रित हैं। स्वीकृत रचनाओं की सूचना दी जाएगी– कैलाश आदमी, संस्थापक संपादक
ईमेल–nirdaliyadaily@gmail.com
वाट्सएप–
९४२४४४३४०१, ८८३९७९७४४८

लघुकथा

प्राथमिकता

सुबह की सैर के बाद जैसे ही विवेक ने कॉलोनी के भीतर कदम रखा मोबाइल की रिंग बजी.... हां दीनबन्धु जी मैं समय पर पहुंच जाऊंगा प्यारे की पटरी पर। चाय सभी साथ पियेंगे ..आप निश्चिन्त रहिए हमको समय का ध्यान है.।

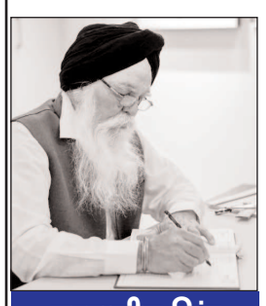

चरणजीत सिंह
कुकरेजा

मुझे पता है तुम वक्त के पाबंद हो। वो तो मैं सबको एक रिमाइन्ड कॉल कर रहा था.... वो क्या है कि नेताजी बड़ी मुश्किल से वक्त देते हैं मिलने का। इसलिए थोड़ा चिंतित हूँ....समय का सब ख्याल नहीं रखते हैं न...

अरे दीनबंधु जी आप टेंशन फ्री होकर तय स्थान पर पहुंचिए। हम सबके हित के लिए ही तो अगुआ बने हैं आप..।आज तो किसी भी सूरत में उन्हें ज्ञापन देकर दो टूक बात करनी ही है। और फिर हमारी मांग भी तो वाजिब है ..

ठीक है मैं निकलता हूं,गोल्डन चाय बनवाता हूं सबके लिए...तुम भी सबको लेकर वहीं पहुंचो। और हां...सब एक एक बुके जरूर ले आना रास्ते से. ...नेताजी को फूलों की खुश्बू बहुत पसंद है..। वैसे भी हम कॉलोनी के उजड़े पार्क को हरा भरा और खूबसूरत बनाने की बात करने ही तो जा रहे हैं...

लो भई आ गए सब.. ..प्यारे दो चाय सबको...जल्दी पहुंचना है नेताजी के घर. चाय की चुस्कियों के बीच ही विवेक बोला दीनबंधु जी अस्थाना जी नहीं आये...आपने उन्हें फोन नहीं किया क्या.... किया था,पर वह कभी कहीं साथ चलता ही नहीं है... जब भी कहीं जाने की बात करो तो पत्नी के अस्वस्थ होने की बात कर मना कर देता है.. । उसी की तीमारदारी में लगा रहता है वह। आज भी बात की तो कहने लगा पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है...तुम लोग चले जाओ... सभी एक स्वर में बोले.. कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं बताया उन्होंने.. सिटी हॉस्पिटल में...नेताजी के घर के रास्ते में ही तो है.... चलो फिर पहले उनकी ही खैर खबर ले लेते है... विवेक ने कहा- नहीं नहीं ऐसे में देर हो जाएगी और नेताजी हमेशा की तरह फिर किसी दूसरे कार्यक्रम में जाने की जल्दी में हमें मिलने की फिर कोई दूसरी तारीख दे कर अपना पल्ला झाड़ लेंगे.। अस्थाना से वापसी में मिल लेंगे...वो तो घर का ही आदमी है.. सब एक मत होते ही गाड़ी में सवार हो नेताजी के घर की ओर रवाना हो गए...

पर ये क्या आज फिर नेताजी के पी.ए ने घर के बाहर अतिथि कक्ष में बिठा कर चाय पकड़ाई और दो घंटे प्रतीक्षा करने का निवेदन कर गायब हो गया। पता चला नेताजी किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हैं। अब आए हैं तो आज उन्हें मिलकर ही जायेंगे चाहे कितना ही इंतजार क्यों न करना पड़े...करीब चार घंटे के बाद पी.ए ने सूचना दी कि नेताजी पार्टी की आकस्मिक मीटिंग के लिए निकल गए हैं..।

सबके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। वापसी पर सबने चाहे अनचाहे सिटी हॉस्पिटल अस्थाना जी की पत्नी की खैरियत पूछने का मन बनाया।

लेकिन वहां पहुंच कर जो खबर लगी उसने सबके होश उड़ा दिए.... रिसेप्शन से पता चला अस्थाना जी की पत्नी थोड़ी देर पहले ही शांत हो गई हैं । सब एक दूसरे के फ़क हुए चेहरे को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे... । सबकी डबडबाती आंखें एक ही इबारत बयान कर रही थी .....

काश!! हम नेताजी जी से पहले अपने मित्रवत रिश्तों को *प्राथमिकता* दे पाते....

-भोपाल

क्या संभव है एक राष्ट्र एक चुनाव?

वीरेंद्र बहादुर सिंह

भारत में चुनाव अब केवल लोकतंत्र का उत्सव नहीं रह गए हैं, बल्कि वे लगातार चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया बन चुके हैं। हर पांच वर्ष में लोकसभा चुनाव और अलग-अलग समय पर होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण देश का कोई न कोई हिस्सा लगभग हमेशा चुनावी माहौल में रहता है। इस लगातार चलने वाले चुनाव चक्र को बदलने के लिए लंबे समय से चर्चा में रहा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है।

इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की योजना है। खास तौर पर 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ बड़ी संख्या में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाओं की चर्चा ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, पहले 2034 से देश के चुनाव चक्र को पूरी तरह एक साथ लाने का विचार था, लेकिन अब 2028 से ही इसकी शुरुआत करने का विकल्प भी विचाराधीन है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से जुड़े प्रस्तावों का अध्ययन संयुक्त संसदीय समिति कर रही है। वर्ष 2024 में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानून में संशोधन के प्रस्ताव समिति को सौंपे गए थे। समिति ने इस विषय पर विभिन्न राज्यों में जाकर मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों, कानून विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है। समिति की रिपोर्ट संसद में पेश करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि 2029 में लोकसभा और अधिकतर राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने हैं, तो यह व्यावहारिक रूप से संभव कैसे होगा?

सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल एक ही समय पर पूरा नहीं होता। कुछ राज्यों में 2026 में चुनाव होने हैं, तो कुछ में 2028 में। वहीं कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव 2029 के बाद होने हैं। ऐसे में यदि 2029 में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने हैं, तो कई राज्यों की मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल निर्धारित समय से पहले समाप्त करना पड़ेगा। एक विकल्प यह है कि राजग शासित राज्यों की कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर उन्हें निर्धारित चुनाव चक्र में शामिल किया जाए। रिपोर्टों में ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या करीब 22 तक होने की बात कही जा रही है।

एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव में राजनीतिक गणित को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि लोकसभा के साथ बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव होते हैं और एनडीए अधिकांश राज्यों में एक साथ चुनाव मैदान में उतरती है, तो भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, विकास और केंद्र सरकार के प्रदर्शन जैसे राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं। इसके विपरीत विधानसभा चुनावों में स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय समस्याओं की भूमिका अधिक होती है। बेरोजगारी, कृषि, पानी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और क्षेत्रीय असंतोष जैसे मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करते हैं। यह मानना सही नहीं होगा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अपने आप भाजपा के लिए चुनाव जीतने की गारंटी बन जाएगा। भारतीय मतदाता कई मौकों पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग-अलग दलों के पक्ष में मतदान कर चुके हैं। मतदाता राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के आधार पर अपना निर्णय अलग-अलग भी कर सकता है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था भाजपा या किसी अन्य दल को राजनीतिक लाभ दे सकती है, लेकिन इसे निश्चित चुनावी परिणाम के रूप में देखना उचित नहीं होगा।

चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान नई नीतियों और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी कुछ सीमाएं आती हैं। लगातार चुनावी माहौल रहने से राजनीतिक दलों और सरकारों पर अल्पकालिक राजनीतिक फैसले लेने का दबाव बढ़ने का तर्क भी दिया जाता है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विरोध कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने से देश के संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है। राज्यों के अपने अलग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे होते हैं। आशंका जताई जाती है कि यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं।

विपक्ष का यह भी तर्क है कि अलग-अलग समय पर चुनाव होने से मतदाताओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रदर्शन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। एक साथ चुनाव होने पर यह स्वतंत्र राजनीतिक मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सामने सबसे गंभीर चुनौती संवैधानिक है। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर जाती है। ऐसी स्थिति में क्या विधानसभा का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा? क्या नई सरकार को केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए चुना जाएगा? या फिर विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराए जाएंगे? इसी तरह यदि किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बनती है और कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता, तो क्या होगा? यही सवाल लोकसभा पर भी लागू होता है। यदि लोकसभा समय से पहले भंग हो जाए तो क्या पूरे देश को फिर से लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनावों की ओर ले जाना होगा? या नई लोकसभा केवल शेष कार्यकाल के लिए काम करेगी? इन सवालों का स्पष्ट संवैधानिक समाधान किए बिना एक साथ चुनाव की व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखना कठिन होगा।

दरअसल, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' केवल चुनाव की तारीख एक करने का विषय नहीं है। यह देश की चुनावी और संवैधानिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है। इसके लिए यह स्पष्ट करना होगा कि सरकार के बीच में गिरने, विधानसभा भंग होने, त्रिशंकु सदन बनने और लोकसभा के समय से पहले भंग होने जैसी परिस्थितियों में क्या व्यवस्था होगी। साथ ही राज्यों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे की रक्षा के सवाल का समाधान भी जरूरी होगा। 2029 में लोकसभा और बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का विचार राजनीतिक दृष्टि से आकर्षक जरूर दिखाई देता है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। मूल विचार 2034 से देश के चुनाव चक्र को पूरी तरह एक साथ लाने का बताया जाता रहा है। अब 2028 से ही प्रक्रिया शुरू करने का विकल्प चर्चा में है। लेकिन इसके लिए कई राज्यों की मौजूदा चुनावी समय-सारणी में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अच्छा विचार है या नहीं, बल्कि यह है कि इसे संविधान, संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ किस तरह लागू किया जा सकता है। 2029 का लक्ष्य राजनीतिक रूप से आकर्षक हो सकता है, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक गणित नहीं, बल्कि संवैधानिक सहमति और व्यावहारिक क्रियान्वयन है।

-नोएडा